



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

No. 160]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 8/2006—सेवा कर

सा.का.नि. 224(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 73ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ ब्याज की दर तेरह प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित करती है।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 8/2006—Service Tax

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by section 73B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby fixes the rate of interest at thirteen per cent. per annum for the purpose of said section.

[F.No.B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 9/2006—सेवा कर

सा.का.नि. 225(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मार्त दिल्ली के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2004—सेवा कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ '(ख)' के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 के तहत भारत के बाहर से उपलब्ध कुराई गई अथवा करवाई जाने वाली तथा भारत में प्राप्त की गई कोई भी कराधेय सेवा।”।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

**टिप्पणि :** मूल अधिसूचना सं. 36/2004-सेवा कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2004 सा.का.नि. 849(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2005-सेवा कर तारीख 7 जून 2005 [सा.का.नि. 366(अ), तारीख 7 जून, 2005] द्वारा किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 9/2006-Service Tax

**G.S.R. 225(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004, G.S.R. 849 (E), dated the 31st December, 2004, namely:-

In the said notification, for paragraph (B), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(B) any taxable service provided or to be provided from a country other than India and received in India, under section 66A of the Finance Act, 1994.”.

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

**Note :** The principal Notification No. 36/2004-Service Tax, dated the 31st December, 2004 was published *vide* number G.S.R. 849(E), dated the 31st December, 2004 and was last amended *vide* Notification No. 24/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005, G.S.R. 366(E), dated the 7th June, 2005.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 10/2006-सेवा कर

**सा.का.नि. 226(अ).**—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (1)

तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा सेवाकर नियमावली, 1994 को संशोधित करने के लिए आगे और निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2006 कहा जाये।

(2) ये इनके सरकारी साजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर नियमावली, 1994 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 2 में, उपनियम (1) में, खंड (घ) में, उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(iv) उक्त वित्त अधिनियम के धारा 66क के तहत भारत के बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाई गई अथवा प्रदान की जाने वाली तथा भारत में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में, ऐसी सेवा प्राप्त करने वाला ;”

3. उक्त नियमावली में, नियम 6 में, उपनियम (8) और (9) का लोप किया जायेगा ।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल नियमावली अधिसूचना सं. 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 5/2006-सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2006 [सा.का.नि. 119(अ), तारीख 1 मार्च, 2006] के तहत संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 10/2006-Service Tax

**G.S.R. 226(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Second Amendment) Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Service Tax Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (d), for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(iv) in relation to any taxable service provided or to be provided by any person from a country other than India and received by any person in India under section 66A of the Act, the recipient of such service;”.

3. In the said rules, in rule 6, sub-rules (8) and (9) shall be omitted.

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* Notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994, G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and was last amended *vide* Notification No. 5/2006-Service Tax, dated the 1st March, 2006, G.S.R. 119(E), dated the 1st March, 2006.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 11/2006-सेवा कर

**सा.का.नि. 227(अ).**—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66क के साथ पठित धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को सेवाओं का करा निर्धारण (भारत के बाहर से प्रदान किए गए और भारत में प्राप्त) नियमावली, 2006 कहा जाए ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) अभिप्रेत है ;  
 (ख) “निविष्टि” का वही अर्थ होगा जो इसे सेनवेट प्रत्यय नियमावली, 2004 के नियम 2 के खंड (ट) में दिया गया है।  
 (ग) “निविष्टि सेवा” का वही अर्थ होगा जो इसे सेनवेट प्रत्यय नियमावली, 2004 के नियम 2 के खंड (1) में दिया गया है।  
 (घ) “उत्पादन सेवा” का वही अर्थ होगा जो इसे सेनवेट प्रत्यय नियमावली, 2004 के नियम 2 के खंड (त) में दिया गया है।

(ङ.) “भारत” के अन्तर्गत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 429 (अ) तारीख 18 जुलाई, 1986 और का.आ. 643 (अ) तारीख 19 सितम्बर, 1996 द्वारा घोषित महाद्वीपीय मण्डल भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र अभिहित हैं ;

(ङ.) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. भारत के बाहर से प्रदान किए गए और भारत में प्राप्त करादेय सेवा।- उक्त वित्त अधिनियम की धारा 66क के प्रावधानों के शर्त पर, भारत के बाहर से प्रदान किए गए और भारत में प्राप्त करादेय सेवाएं।-

(i) जो कि उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (घ), (त), (प), (फ) (यपथ), (ययक), (ययख), (यययग), (यययज) और (यययद) में विनिर्दिष्ट करादेय सेवाएं होंगी और जो भारत में स्थित अचल संपत्ति के संबंध में प्रदान की जायेंगी ;

(ii) जो कि उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (क), (च), (ज), (झ), (अ), (ठ), (ड), (ढ), (ण), (ध), (न), (प), (ब), (भ), (म), (य), (यख), (यग), (यझ), (यञ), (यঠ), (যণ), (যথ), (যঢ), (যন), (যপ), (যফ), (যব), (যযক), (যযগ), (যযঘ), (যযচ), (যযছ), (যযজ), (যযঝ), (যযঠ), (যযড), (যযঢ), (যযণ), (যযত), (যযঘ), (যযন), (যযফ), (যযব), (যযম), (যযম) (যযঘ) (যযঢ) (যযঘ) और (यয়ত) में विनिर्दिष्ट करादेय सेवाएं होंगी और जो कि भारत में प्राप्त की गई हो :

परंतु जब उक्त करादेय सेवा भारत में प्राप्त की गई हो, उसे भारत में प्राप्त किया माना जायेगा और उक्त करादेय सेवा का मूल्य उक्त अधिनियम की धारा 67 तथा इस धारा के तहत बनाए गए नियम के अधीन किया जायेगा;

(iii) जो कि उक्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) में विनिर्दिष्ट हों परंतु  
 (क) उप -खंड (य य य ण) तथा (य य य फ) में विनिर्दिष्ट करादेय सेवाएं;  
 (ख) करादेय सेवाएं जो इन नियमों के खंड (i) में विनिर्दिष्ट हों जबकि खंड (घ), (यয়যগ) और (যয়যদ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं का प्रदान अचल संपत्ति से संबंधित न हों; और  
 (ग) इन नियमों के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर जो कि भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय या वाणिज्य के संबंध में प्राप्त की गई हों।

4. सेवा कर का भुगतान और पंजीकरण. - भारत के बाहर से प्रदान किया गया और भारत में प्राप्त करादेय सेवा को प्राप्त करने वाला पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देगा और इसके लिए धारा 69 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाई गई नियमावली लागू होगी।

5. करादेय सेवा को उत्पाद सेवा नहीं माना जायेगा। - भारत के बाहर से प्रदान किया गया और भारत में प्राप्त किया गया सेवा को केन्द्रीय प्रत्यय नियम 2004 के तहत उत्पाद शुल्क या सेवाकर के प्रत्यय के लिए उत्पाद सेवा नहीं माना जायेगा।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरव्]

आर. श्रीराम, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2006

**No. 11/2006-Service Tax**

**G.S.R. 227(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94, read with section 66A of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Finance Act, 1994 (32 of 1994);
- (b) “input” shall have the meaning assigned to it in clause (k) of rule 2 of the CENVAT Credit Rules, 2004;
- (c) “input service” shall have the meaning assigned to it in clause (l) of rule 2 of the CENVAT Credit Rules, 2004;
- (d) “output service” shall have the meaning assigned to it in clause (p) of rule 2 of the CENVAT Credit Rules, 2004;
- (e) “India” includes the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the notifications of the Government of India in the Ministry of External Affairs numbers S.O. 429 (E), dated the 18<sup>th</sup> July, 1986 and S.O. 643(E), dated the 19<sup>th</sup> September 1996;
- (f) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Taxable services provided from outside India and received in India.— Subject to section 66A of the Act, the taxable services provided from outside India and received in India shall, in relation to taxable services,—

- (i) specified in sub-clauses (d), (p), (q), (v), (zzq), (zzza), (zzzb), (zzzc), (zzzh) and (zzzr) of clause (105) of section 65 of the Act, be such services as are provided or to be provided in relation to an immovable property situated in India;
- (ii) specified in sub-clauses (a), (f), (h), (i), (j), (l), (m), (n), (o), (s), (t), (u), (w), (x), (y), (z), (zb), (zc), (zi), (zj), (zn), (zo), (zq), (zt), (zu), (zv), (zw), (zzc), (zzd), (zzf), (zzg), (zzh), (zzi), (zzi), (zzm), (zzn), (zzo), (zzp), (zzs), (ztt), (zv), (zzw), (zx), (zy), (zzd), (zzze), (zzzf), and (zzzp) of clause (105) of section 65 of the Act, be such services as are performed in India:

Provided that where such taxable service is partly performed in India, it shall be treated as performed in India and the value of such taxable service shall be determined under section 67 of the Act and the rules made thereunder;

1177 GoI/06-2

(iii) specified in clause (105) of section 65 of the Act, but excluding,-

(a) sub-clauses (zzzo) and (zzzv);

(b) those specified in clause (i) of this rule except when the provision of taxable services specified in clauses (d), (zzzc), and (zzzr) does not relate to immovable property; and

(c) those specified in clause (ii) of this rule,

be such services as are received by a recipient located in India for use in relation to business or commerce.

**4. Registration and payment of service tax.**— The recipient of taxable services provided from outside India and received in India shall make an application for registration and for this purpose, the provisions of section 69 of the Act and the rules made thereunder shall apply.

**5. Taxable services not to be treated as output services.**— The taxable services provided from outside India and received in India shall not be treated as output services for the purpose of availing credit of duty of excise paid on any input or service tax paid on any input services under CENVAT Credit Rules, 2004.

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 12/2006-सेवा कर

**सा.का.नि. 228(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 कहा जाये।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभासाएँ- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) अभिप्रेत है;

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) “मूल्य” से अधिनियम की धारा 67 में निर्दित मूल्य अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का जो इनमें परिभासित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभासित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. कराधेय मूल्य को निर्धारण का तरीका - किसी कराधेय सेवा का मूल्य, अधिनियम की धारा 67 के प्रयोजनों के अध्याधीन सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जायेगा।

3. मूल्य निर्धारण का तरीका-धारा 67 के प्रावधानों के अंतर्गत कराधेय सेवा, जहाँ प्राप्त प्रतिफल पूर्णतः या आशिक रूप से धन नहीं हो, का मूल्य निर्धारण सेवा प्रदाता द्वारा निम्न तरीके से किया जायेगा:-

(क) ऐसी कराधेय सेवा का मूल्य व्यापार में समान्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी ही सेवा प्रदान करने के लिए रोपा प्रदाता द्वारा ली गई कुल राशि के बावजूद होंगा और ली गई कुल राशि ही प्रतिफल होगा,

(ख) जहां खंड (क) के अनुसार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सके सेवा प्रदाता ऐसी प्रतिफल के बराबर की धनराशि का निर्धारण करेगा जो किसी भी स्थिति में ऐसी कराधेय सेवा के प्रावधान की लागत से कम नहीं होगी।

4. मूल्य को निररत करना (1) नियम (3) में कुछ भी निहित न होने का अर्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के प्रतिबंधित करने अथवा पूछताछ के लिए बुलाने के शक्ति के रूप में समझा जायेगा ताकि वह यह संतुष्ट हो सके कि दी गई जानकारी अथवा मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में कोई सत्यता है।

(2) जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि सेवा प्रदाता द्वारा ऐसा निर्धारित मूल्य इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो वह ऐसी सेवा प्रदाता को इस बात के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा सेवाकर प्रभारित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे कराधेय सेवा का मूल्य ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार क्यों निर्धारित नहीं किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद अधिनियम और इन नियमों के अनुसार प्रभारित किए जाने वाले सेवा कर के प्रयोजनार्थ ऐसी कराधेय सेवा का मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

5. कतिपय व्यय या खर्चों का मूल्य में अंतर्वेशन या उससे अपवर्जन :- (1) जहां सेवा प्रदाता द्वारा कराधेय सेवा को प्रदान करने के दौरान कोई व्यय या खर्च उपगत किया जाता है वहां ऐसे सभी व्यय और खर्चों को प्रदान की गई या की जाने वाली कराधेय सेवाओं के लिए प्रतिफल माना जाएगा और मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रहते हुए, वे व्यय और खर्च जो सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता के विशुद्ध अभिकर्ता रूप में उपगत करता है, कराधेय सेवा के मूल्य से अपवर्जित किए जाएंगे यदि निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :-

- (i) जब सेवा प्रदाता उपाप्त माल या सेवाओं के लिए तीसरे पक्षकार को संदाय करता है तब वह सेवा प्राप्तक के एक विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है;
- (ii) सेवा प्राप्तक सेवा प्रदाता द्वारा विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में अपनी क्षमता में ऐसे खरीदे गए उपाप्त माल या सेवाओं को प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है;
- (iii) सेवा प्राप्तक तीसरे पक्षकार को संदाय करने का उत्तरदायी है;
- (iv) सेवा प्राप्तक सेवा प्रदाता को अपनी ओर से संदाय करने के लिए प्राधिकृत करता है;
- (v) सेवा प्राप्तक यह जानता है कि वे माल और सेवाएं जिनके लिए सेवा प्रदाता को संदाय किया गया है, तीसरे पक्षकार द्वारा प्रदान की जाएंगी;
- (vi) सेवा प्राप्तक की ओर से सेवा प्रदाता के द्वारा किए गए भुगतान को सेवा प्राप्तक को सेवा प्रदाता द्वारा जारी बीजक में पृथक रूप से दर्शित किया गया है जब वह सेवा प्राप्तक को बीजक देता है;
- (vii) सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तक से उतनी ही राशि लेता है जितनी राशि उसने तीसरे पक्षकार को संदत्त की है; और
- (viii) सेवा प्रदाता द्वारा तीसरे पक्ष से सेवा प्राप्तक के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में खरीदा गया माल अथवा सेवाएं उसकी ओर से प्रदान सेवाओं के अतिरिक्त है।

स्पष्टीकरण 1 - उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, “विशुद्ध अभिकर्ता” वह व्यक्ति है जो -

- (क) अपने ग्राहक (सेवा प्राप्तक) के साथ कराधेय सेवा प्रदान करने के दौरान व्यय या खर्च उपगत करने के लिए ग्राहक के विशुद्ध अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का संविदात्मक करार करता है;
- (ख) सेवा प्राप्तक के विशुद्ध के अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार खरीदे गए अथवा प्रदान किए गए माल या सेवाओं पर कोई शीर्षक रखने का न तो उसका इरादा और न ही रखता हो;
- (ग) प्रदान किए गए ऐसे माल या सेवाओं का कभी उपयोग नहीं करता है; और
- (घ) ऐसे माल या सेवाओं को उपाप्त करने के लिए उपगत वास्तविक रकम प्राप्त करता है।

**स्पष्टीकरण 2 -** इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कराधेय सेवा का मूल्य ऐसी कराधेय सेवा के लिए प्रतिफल की कुल रकम है जिसमें कराधेय सेवा का एक या अधिक संघटक सम्मिलित है और कुल प्रतिफल के ऐसे संघटकों के ब्यौरे, चाहे बीजक में पृथक रूप से उपदर्शित किए गए हों अथवा नहीं, कराधेय मूल्य के अवधारण के प्रयोजन के लिए सुसंगत नहीं हैं।

**दृटांत 1 -** X, Y के साथ, जो संपदा अभिकर्ता है, अपना घर बेचने के लिए संविदा करता है और उस पर Y टेलीविजन में एक विज्ञापन देता है। Y, X को बिल देता है जिसमें समाचार पत्र में विज्ञापन के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं और बिल के कुल प्रतिफल पर सेवाकर का संदाय करता है। ऐसी दशा में प्रदान की गई सेवा के लिए प्रतिफल वह है जो X, Y को संदाय करता है। X यह दलील नहीं दे सकता है कि Y ने उसकी ओर से उस समय अभिकर्ता के रूप में कार्य किया था जब वह समाचार पत्र में विज्ञापन अभिप्राप्त कर रहा था। भले ही टेलीविजन में विज्ञापन का खर्च बिल में पृथक रूप से वर्णित है। ऐसी सेवाएं संपदा अभिकर्ता के लिए, संपदा अभिकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देने में समर्थ बनाने या सुकर बनाने के लिए निवेश सेवाओं की प्रकृति की हैं।

**दृटांत 2 -** कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता खर्च जैसे कि यात्रा-व्यय, डाक-महसूल, टेलीफोन आदि पर कराधेय सेवा प्रदान करने के दौरान उपगत करता है और इन मदों को सेवा प्राप्तक को बीजक में पृथक रूप से उपदर्शित कर सकेगा। ऐसी दशा में सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तक के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर रहा है किन्तु कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए अपनी ओर से निवेश या निवेश सेवा उपाप्त करता है। मात्र इसलिए कि बीजक में ऐसे व्ययों को पृथक रूप से दर्शित किया गया है, इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वे प्रतिपूर्ति किए जाने वाले व्यय नहीं हैं।

**दृटांत 3 -** A, B के साथ जो एक वास्तुविद है, भकान बनाने की संविदा करता है। कराधेय सेवा प्रदान करने के दौरान B टेलीफोन प्रभारों, हवाई यात्रा टिकटों, होटल आवास आदि पर व्यय उपगत करता है जिससे कि वह A को सेवा के उपबंध को पूरा करने के लिए प्रभावी रूप से समर्थ हो सके। ऐसी दशा में B जिस रूप में भी A से ऐसे व्यय की वसूली करता है, चाहे वह उन्हें पृथक पृथक मद के व्यय के रूप में दर्शित करता है या संपूर्ण फीस के रूप में दर्शित करता है वहां सेवा कर B द्वारा प्रभारित कुल रकम पर सेवा कर संदेय है। यह बात विल्कुल ही महत्वहीन है कि सेवा प्रदाता किस तरह अपने बीजक या बिल में उन प्रभारों को संगणित करता है या दिखाता है। सेवा के लिए प्रतिफल वह है जो A, B को संदाय करता है और वही सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कराधेय मूल्य है।

**दृटांत 4 -** कंपनी X किराए के कैब की कराधेय सेवा उपलब्ध कराने के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए मोटर चालक उपलब्ध कराती है। मोटर चालक को पर्यटन के दौरान उसके भोजन और रात्रि आवास तथा किन्हीं अन्य आनुंगिक व्ययों जैसे पार्किंग फीस की पूर्ति के लिए एकमुश्त रकम दी जाती है। पर्यटन की समाप्ति पर वह शो रकम को अपने व्ययों के लेखा विवरण और सुसंगत बिलों सहित वापस करता है। कंपनी X ने इन रकमों को सेवाप्राप्त करने वालों से प्रभारित किया है। ऐसी दशा में, मोटर चालक द्वारा उपगत लागत और सेवाप्राप्त करने वाले को दिए गए बिल कंपनी द्वारा सेवाओं के उपलब्ध कराने के लिए प्रतिफल का भाग गठित करते हैं।

6. वे मामले जिनमें कमीशन, लागत आदि, सम्मिलित या अपवर्जित की जाएंगी - (1) धारा 67 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कराधेय सेवाओं के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

- (i) दलाल द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय पर प्रभारित कमीशन या दलाली इसके अन्तर्गत स्टाक दलाल द्वारा किसी उप दलाल को संदत कमीशन या दलाली भी है;
- (ii) अभिदाता द्वारा टेलीफोन कनैक्शन या पेजर या अनुकृति या टेलीग्राफ या टैलेक्स या पट्टाधृत सर्किट के लिए आवेदन के समय किए गए किन्हीं निष्केपों में से टेलीग्राफ प्राधिकारी द्वारा किए गए समायोजन ;
- (iii) पालिसी धारक से बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित प्रीमिशन की रकम;
- (iv) वायुयान यात्रा अभिकर्ता द्वारा एयरलाइन्स द्वारा प्राप्त कमीशन ;

- (v) किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त कमीशन, फीस या कोई अन्य धनराशि ;
- (vi) प्राधिकृत सेवा केन्द्र द्वारा विनिर्माता से ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटर कार, हल्के मोटर यान या दोपहिया मोटर यान से की गई किसी सेवा के लिए प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति ;
- (vii) रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा रेलवे या ग्राहक से प्राप्त किया गया कमीशन या कोई रकम;
- (viii) ऐसे अभिकर्ता को किसी निकासी या अग्रेण अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहक द्वारा ऐसे अभिकर्ता को नियोजित करके किसी रीति में निकासी या अग्रेण सेवाएं प्रदान करने वाले ग्राहक को संदत्त किसी नाम से ज्ञात पारिश्रमिक या कमीशन ;
- (ix) किसी भी नाम से ज्ञात कमीशन, फीस या कोई अन्य धनराशि, जिसका बीमांकर्ता द्वारा किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई बीमा आनुगिक सेवाओं के संबंध में ऐसे अभिकर्ता की नियुक्ति करके संदाय किया गया है।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विट उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी कराधेय सेवा के मूल्य में, यथास्थिति, निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं-

- (i) अभिदाता द्वारा टेलीफोन कनैक्शन या पेजर या अनुकृति या टेलीग्राफ या टैलेक्स या पट्टाधृत सर्किट के लिए आवेदन के समय किया गया आरम्भिक निष्केप ;
- (ii) वायुयात्रा अभिकर्ता द्वारा उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत संग्रह किया गया वायुयान किराया ;
- (iii) वायुयात्रा अभिकर्ता द्वारा उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत संग्रह किया गया रेल किराया ;
- (iv) ऋणों पर व्याज ।

7. वास्तविक प्रतिफल का भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा के मूल्य के रूप में होना (1) - धारा 66क के उपबन्धों के अधीन प्राप्त कराधेय सेवा के मूल्य को ऐसी रकम के रूप में लिया जाएगा मानो जो उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित वास्तविक प्रतिफल के बराबर होगा।
- (2) उपर्युक्त उपनियम (1) में किसी बात के निहित होते हुए भी सेवाओं के कराधान (भारत से बाहर से प्राप्त की गई अथवा भारत में प्राप्त) नियम, 2006 के नियम (3) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं का मूल्य जो आंशिक रूप से भारत में निष्पादित किया गया हो, भारत से बाहर आंशिक रूप से निष्पादित सेवा के मूल्य सहित, ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा संदत्त कुल प्रतिफल होगा।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 12/2006-Service Tax

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006.

• 1177 GJ/06-3

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Finance Act, 1994 (32 of 1994);
- (b) “section” means the section of the Act;
- (c) “value” shall have the meaning assigned to it in section 67;
- (d) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Manner of determination of value.— Subject to the provisions of section 67, the value of taxable service, where the consideration received is not wholly or partly consisting of money, shall be determined by the service provider in the following manner:—

- (a) the value of such taxable service shall be equivalent to the gross amount charged by the service provider to provide similar service to any other person in the ordinary course of trade and the gross amount charged is the sole consideration;
- (b) where the value cannot be determined in accordance with clause (a), the service provider shall determine the equivalent money value of such consideration which shall, in no case be less than the cost of provision of such taxable service.

4. Rejection of value.— (1) Nothing contained in rule 3 shall be construed as restricting or calling into question the power of the Central Excise Officer to satisfy himself as to the accuracy of any information furnished or document presented for valuation.

(2) Where the Central Excise Officer is satisfied that the value so determined by the service provider is not in accordance with the provisions of the Act or these rules, he shall issue a notice to such service provider to show cause why the value of such taxable service for the purpose of charging service tax should not be fixed at the amount specified in the notice.

(3) The Central Excise Officer shall, after providing reasonable opportunity of being heard, determine the value of such taxable service for the purpose of charging service tax in accordance with the provisions of the Act and these rules.

5. Inclusion in or exclusion from value of certain expenditure or costs.— (1) Where any expenditure or costs are incurred by the service provider in the course of providing taxable service, all such expenditure or costs shall be treated as consideration for the taxable service provided or to be provided and shall be included in the value for the purpose of charging service tax on the said service.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the expenditure or costs incurred by the service provider as a pure agent of the recipient of service, shall be excluded from the value of the taxable service if all the following conditions are satisfied, namely:—

- (i) the service provider acts as a pure agent of the recipient of service when he makes payment to third party for the goods or services procured;
- (ii) the recipient of service receives and uses the goods or services so procured by the service provider in his capacity as pure agent of the recipient of service;
- (iii) the recipient of service is liable to make payment to the third party;

- (iv) the recipient of service authorises the service provider to make payment on his behalf;
- (v) the recipient of service knows that the goods and services for which payment has been made by the service provider shall be provided by the third party;
- (vi) the payment made by the service provider on behalf of the recipient of service has been separately indicated in the invoice issued by the service provider to the recipient of service;
- (vii) the service provider recovers from the recipient of service only such amount as has been paid by him to the third party; and
- (viii) the goods or services procured by the service provider from the third party as a pure agent of the recipient of service are in addition to the services he provides on his own account.

*Explanation 1.*—For the purposes of sub- rule (2), “pure agent” means a person who—

- (a) enters into a contractual agreement with the recipient of service to act as his pure agent to incur expenditure or costs in the course of providing taxable service;
- (b) neither intends to hold nor holds any title to the goods or services so procured or provided as pure agent of the recipient of service;
- (c) does not use such goods or services so procured; and
- (d) receives only the actual amount incurred to procure such goods or services.

*Explanation 2.*— For the removal of doubts it is clarified that the value of the taxable service is the total amount of consideration consisting of all components of the taxable service and it is immaterial that the details of individual components of the total consideration is indicated separately in the invoice.

*Illustration 1.*— X contracts with Y, a real estate agent to sell his house and thereupon Y gives an advertisement in television. Y billed X including charges for Television advertisement and paid service tax on the total consideration billed. In such a case, consideration for the service provided is what X pays to Y. Y does not act as an agent behalf of X when obtaining the television advertisement even if the cost of television advertisement is mentioned separately in the invoice issued by X. Advertising service is an input service for the estate agent in order to enable or facilitate him to perform his services as an estate agent

*Illustration 2.*— In the course of providing a taxable service, a service provider incurs costs such as traveling expenses, postage, telephone, etc., and may indicate these items separately on the invoice issued to the recipient of service. In such a case, the service provider is not acting as an agent of the recipient of service but procures such inputs or input service on his own account for providing the taxable service. Such expenses do not become reimbursable expenditure merely because they are indicated separately in the invoice issued by the service provider to the recipient of service.

*Illustration 3.*— A contracts with B, an architect for building a house. During the course of providing the taxable service, B incurs expenses such as telephone charges, air travel tickets, hotel accommodation, etc., to enable him to effectively perform the provision of services to A. In such a case, in whatever form B recovers such expenditure from A, whether as a separately itemised expense or as part of an inclusive overall fee, service tax is payable on the total amount charged by B. Value of the taxable service for charging service tax is what A pays to B.

*Illustration 4.*— Company X provides a taxable service of rent-a-cab by providing chauffeur-driven cars for overseas visitors. The chauffeur is given a lump sum amount to cover his food and overnight accommodation and any other incidental expenses such as parking fees by the Company X during the tour. At the end of the tour, the chauffeur returns the balance of the amount with a statement of his expenses and the relevant bills. Company X charges these amounts from the recipients of service. The cost incurred by the chauffeur and billed to the recipient of service constitutes part of gross amount charged for the provision of services by the company X.

6. Cases in which the commission, costs, etc., will be included or excluded.—(1) Subject to the provisions of section 67, the value of the taxable services shall include,—

- (i) the commission or brokerage charged by a broker on the sale or purchase of securities including the commission or brokerage paid by the stock-broker to any sub-broker;
- (ii) the adjustments made by the telegraph authority from any deposits made by the subscriber at the time of application for telephone connection or pager or facsimile or telegraph or telex or for leased circuit;
- (iii) the amount of premium charged by the insurer from the policy holder;
- (iv) the commission received by the air travel agent from the airline;
- (v) the commission, fee or any other sum received by an actuary, or intermediary or insurance intermediary or insurance agent from the insurer;
- (vi) the reimbursement received by the authorised service station, from manufacturer for carrying out any service of any motor car, light motor vehicle or two wheeled motor vehicle manufactured by such manufacturer;
- (vii) the commission or any amount received by the rail travel agent from the Railways or the customer;
- (viii) the remuneration or commission, by whatever name called, paid to such agent by the client engaging such agent for the services provided by a clearing and forwarding agent to a client rendering services of clearing and forwarding operations in any manner; and
- (ix) the commission, fee or any other sum, by whatever name called, paid to such agent by the insurer appointing such agent in relation to insurance auxiliary services provided by an insurance agent.

(2) Subject to the provisions contained in sub-rule (1), the value of any taxable service, as the case may be, does not include—

- (i) initial deposit made by the subscriber at the time of application for telephone connection or pager or facsimile (FAX) or telegraph or telex or for leased circuit;
- (ii) the airfare collected by air travel agent in respect of service provided by him;
- (iii) the rail fare collected by air travel agent in respect of service provided by him; and
- (iv) interest on loans.

7. Actual consideration to be the value of taxable service provided from outside India.—(1) The value of taxable service received under the provisions of section 66A, shall be such amount as is equal to the actual consideration charged for the services provided or to be provided.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the value of taxable services specified in clause (ii) of rule 3 of Taxation of Services (Provided from Outside India and Received in India) Rules, 2006, as are partly performed in India, shall be the total consideration paid by the recipient for such services including the value of service partly performed outside India.

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 13/2006-सेवा कर

**सा.का.नि. 229(अ).**—वित्त अधिनमय, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 और 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केन्द्रीय सरकार सेवा निर्यात नियमावली, 2005 को और आगे संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को सेवाओं का निर्यात नियमावली, 2006 कहा जाए।  
 (2). ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवाओं के निर्यात नियमावली, 2005 में (एतदपश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) प्रस्तावना में शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों “धारा 94 की उपधारा (1) और उपधारा (2)” को शब्दों और आंकड़ों “धारा 93 और 94” से प्रतिस्थापित किया जाये।

3. उक्त नियमावली में नियम 3 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिरक्षापित किया जाए, अर्थातः-

“ 3. कराधेय सेवा का निर्यात- (1) (i) अधिनियम की धारा 65 के खंड 105 के उपखंड (घ), (त), (प), (यथ), (ययक), (ययख), (ययग), (ययज) तथा (ययद) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के संबंध में, जो भारत से बाहर स्थित अचल संपत्ति के संबंध में सेवाएं प्रदान की जाती हैं वही सेवाएं उपलब्ध करवाना सेवा का निर्यात होगा ।

(ii) अधिनियम की धारा 65 खंड (105) के उपखंड (क), (च), (ज), (झ), (ञ), (ठ), (ડ), (ਠ), (ਣ), (ਧ), (ਨ), (ਪ), (ਬ), (ਮ), (ਯ), (ঘঢ়), (ঘগ), (ঘঝ), (ঘজ), (ঘঢ়), (ঘণ), (ঘথ), (ঘদ), (ঘন), (ঘন), (ঘপ), (ঘফ), (ঘব), (ঘয়ক), (ঘয়গ), (ঘয়ঘ), (ঘয়চ), (ঘয়ছ), (ঘয়জ), (ঘয়ঝ), (ঘয়ঞ), (ঘয়ঞ্জ), (ঘয়ঞ্জ), (ঘয়ঠ), (ঘয়ঘচ) ও (ঘয়ঘত) মেঁ বিনির্দিষ্ট করাধৈয় সেবাওঁ কে সংবন্ধ মেঁ জো ভাৰত সেঁ বাহেৰ সেবাএঁ নিষ্পাদিত কী জাতী হৈঁ বহু সেবাএঁ উপলব্ধ কৰখানা সেবা কা নিৰ্যাত হোৱা ।

बशर्ते कि जब ऐसी कराधय सेवा आंशिक रूप से भारत से बाहर निष्पादित की जाती है तो इसे भारत से बाहर निष्पादित किया गया माना जाएगा ।

(iii) धारा 65 के खंड (105) के

(क) उपखंड (यथयण) तथा (यथयफ)

(ख) इस नियम के खंड (i) में विनिर्दिष्ट सेवाओं बशर्ते कि उपखंड (घ), (यययग) और (यययद) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाएं अचल संपत्ति से संबंधित नहीं हो; और

(ग) इस नियम के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट

सेवाओं को छोड़कर अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) में विनिर्दिष्ट सेवाएं जब सेवाएं व्यवसाय अथवा वाणिज्य के संबंध में जो तो भारत से बाहर स्थित सेवा प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाए तो सेवा का

1177 GI 106-4

निर्यात होगा और ऐसी सेवाएं प्रदान करते समय भारत से बाहर स्थित प्राप्तकर्ता को सेवाएं उपलब्ध करवाना सेवा का निर्यात होगा।

परंतु यदि सेवा प्राप्तकर्ता का वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अथवा उससे जुड़ा कोई कार्यालय भारत में हो ऐसी कराधेय सेवाओं को सेवा का निर्यात तभी माना जाएगा जब ऐसी सेवा के प्रावधान का आदेश उसके वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अथवा भारत से बाहर स्थित कार्यालय से किया जाए।

(2) किसी कराधेय सेवा के प्रावधान को सेवा का निर्यात तभी माना जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, अर्थात्

- (क) ऐसी सेवा भारत से बाहर प्रदान की जाती है तथा भारत के बाहर उपयोग की जाती है; तथा
- (ख) सेवा प्रदाता प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के लिए “भारत” में विदेश मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं एस.ओ. 429 (ई), दिनांक 18 जुलाई, 1986 और एस.ओ. 643 (ई) दिनांक 19 सितम्बर, 1996 के द्वारा घोषित भारत के कॉटिनेन्टल शेल्फ में निर्धारित क्षेत्र और विशिताष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल होंगे।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं. 9/2005—सेवा कर, तारीख 3 मार्च, 2005, सा.का.नि. 151(अ), तारीख 3 मार्च, 2005 के तहत अधिसूचित किए गए थे और अनुवर्ती रूप से अधिसूचना सं. 28/2005—सेवाकर तारीख 7 जून, 2005, सा.का.नि. 370(अ), तारीख 7 जून, 2005 के तहत संशोधित किए गए थे।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 13/2006-Service Tax

**G.S.R. 229(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 93 and 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Services Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Services (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Services Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in the preamble, for the words, brackets and figures “ sub-section (1) and sub-section (2) of section 94”, the word ~~and~~ figures “sections 93 and 94” shall be substituted:

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Export of taxable service.— (1) Export of taxable services shall, in relation to taxable services,—

(i) specified in sub-clauses (d), (p), (q), (v), (zzq), (zzza), (zzzb), (zzzc), (zzzh) and (zzzr) of clause (105) of section 65 of the Act, be provision of such services as are provided in relation to an immovable property situated outside India;

(ii) specified in sub-clauses (a), (f), (h), (i), (j), (l), (m), (n), (o), (s), (t), (u), (w), (x), (y), (z), (zb), (zc), (zi), (zj), (zn), (zo), (zq), (zr), (zt), (zu), (zv), (zw), (zza), (zzc), (zzd), (zzf), (zzg), (zzh), (zzi), (zzl), (zzm), (zzn), (zzo), (zzp), (zzs), (zzt), (zzv), (zzw), (zzx), (zzy), (zzd), (zzze), (zzzf) and (zzzp) of clause (105) of section 65 of the Act, be provision of such services as are performed outside India:

Provided that where such taxable service is partly performed outside India, it shall be treated as performed outside India;

(iii) specified in clause (105) of section 65 of the Act, but excluding,—

(a) sub-clauses (zzzo) and (zzzv);

(b) those specified in clause (i) of this rule except when the provision of taxable services specified in sub-clauses (d) (zzzc) and (zzzr) does not relate to immovable property; and

(c) those specified in clause (ii) of this rule,

when provided in relation to business or commerce, be provision of such services to a recipient located outside India and when provided otherwise, be provision of such services to a recipient located outside India at the time of provision of such service:

Provided that where such recipient has commercial establishment or any office relating thereto, in India, such taxable services provided shall be treated as export of service only when order for provision of such service is made from any of his commercial establishment or office located outside India.

(2) The provision of any taxable service shall be treated as export of service when the following conditions are satisfied, namely:—

(a) such service is delivered outside India and used outside India; and

(b) payment for such service provided outside India is received by the service provider in convertible foreign exchange.

**Explanation.—** For the purposes of this rule “India” includes the designated areas in the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India as declared by the notifications of the Government of India in the Ministry of External Affairs numbers S.O. 429(E), dated the 18<sup>th</sup> July, 1986 and S.O. 643(E), dated the 19<sup>th</sup> September 1996.”

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were notified *vide* Notification No. 9/2005-Service Tax, dated the 3rd March, 2005, G.S.R. 151(E), dated the 3rd March, 2005 and was subsequently amended *vide* Notification No. 28/2005-Service Tax, dated the 7th June, 2005, G.S.R. 370(E), dated the 7th June, 2005.

1177 GI/06-5

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 14/2006-सेवा कर

**सा.का.नि. 230(अ).**—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार (वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उनके निष्ठभावन से पहले की गई अथवा करने के लिए छोड़ दी गई चीजों को छोड़कर, रद्द करती है, अर्थात् :-

## सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख
(1)	(2)
1.	22/2005 सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005, सा.का.नि. 364 (अ), दिनांक 7 जून, 2005
2.	25/2005 सेवा कर, तारीख 7 जून, 2005, सा.का.नि. 367 (अ), दिनांक 7 जून, 2005

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 14/2006-Service Tax

**G.S.R. 230(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

## Table

S. No.	Notification number and date
(1)	(2)
1.	No. 22/2005-Service Tax, dated the 7 <sup>th</sup> June, 2005, G.S.R. 364(E), dated the 7 <sup>th</sup> June, 2005;
2.	No. 25/2005-Service Tax, dated the 7 <sup>th</sup> June, 2005, G.S.R. 367(E), dated the 7 <sup>th</sup> June, 2005.

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 8/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

**सा.का.नि. 231(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1)

की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32), की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियमावली, 2004 का और आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1)इन नियमों द्वारा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (तीराया संशोधन) नियमावली, 2006 कहा जाए।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियमावली 2004 में नियम 2 में, खंड (त) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. बी 1/4/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

**टिप्पणि :** मूल अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) तारीख 10 सितम्बर, 2004, के तहत अधिसूचित तथा [सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004] के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, तथा इसे अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 6/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) तारीख 20 मार्च, 2006, [सा.का.नि. 169(अ), तारीख 20 मार्च, 2006] के तहत संशोधित की गई थी।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 8/2006-Central Excise (N.T.)

**G.S.R. 23<sup>1</sup>(E).**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 2, in clause (p), the 'Explanation' shall be omitted.

[F. No. B1/4/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* Notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, G.S.R. 600(E), dated 10th September, 2004 and was last amended *vide* Notification No. 6/2006-Central Excise (N.T.), dated the 20th March, 2006, G.S.R. 169(E), dated 20th March, 2006.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सं. 35/2006-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 232(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 (सा.का.नि. 85 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006) को विखंडित करती है।

[फा. सं. 334/3/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2006

No. 35/2006-Customs

**G.S.R. 232(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2006-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2006, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.85(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2006.

[F. No. 334/3/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.